भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**राज्य सभा**

**तारांकित प्रश्न संख्या \*376**

(जिसका उत्तर 03 अप्रैल, 2018/13 चैत्र, 1940 (शक) को दिया जाना है)

**सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विराष्ट्रीयकरण**

376. श्री मानस रंजन भूनियाः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश के सरकारी क्षेत्र के राष्ट्रीयकृत बैंकों के विराष्ट्रीयकरण के लिए गम्भीरतापूर्वक योजना बना रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या योजना है;

(ख) सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विराष्ट्रीयकरण सरकार, जनता और समग्र रूप से देश के लिए किस प्रकार लाभकारी होगा; और

(ग) आज की तारीख तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों की कुल कितनी देनदारियां हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्री (श्री अरुण जेटली)

**(क) से (ग):** एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**‘‘सरकारी क्षेत्र के बैंकों का विराष्ट्रीयकरण” के संबंध में श्री मानस रंजन भूनिया द्वारा पूछे गए 03 अप्रैल, 2018 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या \*376 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण।**

**(क) से (ग):** राष्ट्रीयकृत बैंकों को विराष्ट्रीयकृत करने का कोई प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन नहीं है।

सरकारी क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) के द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार, दिनांक 31.12.2017 की स्थिति के अनुसार, पीएसबी की समग्र देयता 95,92,887 करोड़ रुपए है। देयताओं में उनकी पूंजी, आरक्षित निधि तथा अतिरिक्त निधि, जमाराशि और उधार शामिल हैं।

\*\*\*\*\*